वैल्यू अनलॉक निजी पूंजी का हो इस्तेमाल

अतिथि देवो भवः वैश्विक पर्यटन केंद्र बनना आसान

अनिल अग्रवाल
चेयरमैन, वेदांता समूह

हमारा भारत ऐसा देश होना चाहिए, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हों। भारत के पास जो विरासत, संस्कृति, प्रकृति, आध्यात्मिक संपदा और विविधता है, वो किसी अन्य देश में नहीं है। भारतीय उत्कृष्ट मेजबान भी हैं। हम वैदिक काल से 'अतिथि देवो भवः' और 'वसुधैव कुटुंबकम' में विश्वास करते आए हैं। अर्थव्यवस्था, उद्यमिता और रोजगार सृजन में पर्यटन का योगदान किसी भी अन्य सेक्टर से ज्यादा हो सकता है। इस मामले में एकमात्र कमी हमारे टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर में है। इसका हल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ज्यादा निजी भागीदारी और सरकार का विकेंद्रीकृत नजरिया बहुत बड़ी वैल्यू को अनलॉक कर सकता है।

पर्यटन बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में सक्षम है। यह ऐसा सेक्टर है, जहां बड़ी तादाद में काम करने वाले लोगों की जरूरत होगी।

विश्व पर्यटन संगठन के मुताबिक, अभी हर साल जितने विदेशी भारत आते हैं, उससे ज्यादा भारतीय विदेश जाते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे छोटे देशों में हर साल भारत से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे पास कितना बड़ा मौका है। हर साल सिर्फ 70 लाख अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के बजाय हम 5-10 करोड़ पर्यटक आकर्षित कर सकते हैं, जैसा कि पर्यटन में अव्वल देशों में होता है। पर्यटन हमारे जीडीपी में करीब 6% योगदान करता है। इसे विकसित देशों के मानकों पर खरा उतरकर आसानी से दोगुना किया जा सकता है।

जब लोग ये तय करते हैं कि छुट्टियों में कहां जाना है तो उनके पास ढेरों विकल्प होते हैं। इसलिए अग्रणी पर्यटन केंद्र बनने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्वालिटी, सुविधा और सुरक्षा के वैश्विक मानक अपनाना है। भारत को प्रतिस्पर्धी बनना होगा। पर्यटक स्थलों पर सभी बजट के यात्रियों के लिए अलग-अलग स्टार कैटेगरी के वर्ल्ड क्लास होटल होने चाहिए। पर्याप्त संख्या में अच्छे एयरपोर्ट होने चाहिए। इसके अलावा हवाई मार्ग से सस्ती कनेक्टिविटी की भी जरूरत है। हमें उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं और तेज ट्रेनों के साथ आधुनिक रेलवे स्टेशनों की दरकार है। साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे भी होने चाहिए। और हां, सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, न सिर्फ पुलिस की मौजूदगी के संदर्भ में, बल्कि लाइटिंग सिस्टम जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी।

आज की तारीख में देश का पर्यटन मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण में है। हालांकि केंद्र ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए हैं, लेकिन अब निजीकरण के मामले में बड़े बदलाव पर विचार का समय आ गया है। पर्यटन के निजीकरण से प्रतिस्पर्धा, नयापन और दक्षता बढ़ेगी। इससे ज्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे। कुछ हेरिटेज साइट्स पर सरकार ने संचालन और रखरखाव का काम निजी कंपनियों को सौंपा है। इसे 'एक स्मारक गोद लें' स्कीम के जरिये बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना चाहिए। हां सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि कोई एक या दो पार्टियां साइट्स के बड़े हिस्से पर कब्जा न कर लें। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से चलाए जा रहे होटलों को लंबी लीज पर प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। सरकार को होटल चलाने की जरूरत नहीं है। राज्यों को पर्यटन क्षमता वाले क्षेत्रों में निजी निवेश आकर्षित करना चाहिए। होटलों और रिजॉर्ट्स के लिए अनुकूल शर्तों पर जमीन लीज पर दी जा सकती है। निजीकरण के लिए चुनिंदा एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। इसमें भी तेजी लाई जानी चाहिए। छोटे और दूरदराज के इलाकों को भी बड़े टूरिज्म हब बनाया जा सकता है।

अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि राज्य पर्यटन में अग्रणी भूमिका निभाएंगे और केंद्र सहायक की भूमिका में रहेगा। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और ब्रांडिंग के लिए राज्यों को ब्याज-मुक्त कर्ज दिया जाएगा। राज्यों में पर्यटन सुविधाओं की रेटिंग की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये सही अप्रोच है। राज्यों द्वारा आगे डिसेंट्रलाइजेशन पर विचार किया जा सकता है। ये भी संभव है कि हर जिले को टूरिज्म को प्रमोट करने की योजना बनाने को कहा जाए। उनके आइडिया के आधार पर राज्य सरकार जिलों को धन मुहैया करा सकती है। जिला प्रशासन इस फंडिंग का इस्तेमाल स्थानीय उद्यमियों, खास तौर पर युवाओं को सपोर्ट देने में कर सकता है।

हमारा ये भी मानना है कि पर्यटन बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है, जहां बड़ी संख्या में काम करने वाले लोगों की जरूरत होगी। पर्यटन उद्योग में पहले से 3 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। ये पांच गुना हो सकता है। पर्यटन विदेशी आय का प्रमुख स्रोत भी है। इसे रफ्तार देने की जिम्मेदारी सरकार के बजाय उद्यमियों पर डाला जाना चाहिए। टूरिज्म सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का स्वागत करके भारत आसानी से दुनिया के उन टॉप-3 देशों में शुमार हो सकता है, जहां सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी आते हैं।